as emerging issues in the health sector for consideration of the Regional State Health Ministers' Conferences organised during the period June to November, 1998 at Hyderabad, Shillong, Sringar Ahmedabad and Calcutta.

There was a broad endorsement of the need to review the Health Policy with a view to addressing existing problems and future challenges. It was recommended inter-alia that an effective system for disease surveillance should be established, measures taken to upgrade the rural health infrastructure and to improve access to health services. The need to address the emerging health problems related to non-communicable diseases was also emphasised.

Recommendations were also made to formulate policies which would improve availability of personnel at the Primary Health Centres and rural hospitals and which would foster decentralisaton of health care services. Suggestions were also made to strengthen the enforcement machinery for the prevention of food adulteration and drug control, particularly at the State level; rational development of medical manpower to ensure availability of specialised and skilled professionals in underserved areas; harnessing the capacity of the private sector to augment the supply of essential health services; regulation of private facilities and insistence on proper standards, convergence of programmes relating to drinking water, urban waste disposal and air and water pollution and health to maximise the output from the process of development.

Upgradation of CGHS Pharmacists

*252. SHRI PRAKANTA WARISA: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that 25 per cent Pharmacists to CGHS in the pay scale of Rs. 4500-7000 have been recently upgraded to Senior Pharmacists in the pay scale of Rs. 5000-8000; if so, the reasons therefor;

(b) the number of Pharmacists working at present in Delhi under different systems of medicines, benefited by this upgradation, with the date; and

(c) what are the reasons for not considering promotional posts to the above upgraded posts?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI DALIT EZHILMALAI): (a) Yes, Sir. The reason for upgradation of the posts of Pharmacists is that there was no promotional avenue in the category of Pharmacists.

(b) The requisite information is given in statement. (*see* below).

(c) The upgraded Pharmacists who have been designated as Senior Pharmacists are performing the same duties and responsibilities as are being performed by other Pharmacists. Hence, the posts of Senior Pharmacists have not been considered as promotional posts.

Statement

Name of system	Number	Date
Allopathic	82	11.7.95
	3	1.8.95
	5	1.12.95
	1	1.4.96
	1	1.9.96
	1	1.1.97
	1	1.2.97
	1	1.6.97
Ayurvedic	9	11.7.95
Unani	2	11.7.95
Homoeopathic	5	11.7.95

बाल साहित्य अकादमी का गठन

*253. श्रीमती सरोज दुबे: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार राष्ट्रीय स्तर पर बाल साहित्य अकादमी का गठन करेगी;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी): (क) से (ग) जी, नहीं। सरकार किसी बाल साहित्य अकादमी को स्थापित करना आवश्यक नहीं समझती है क्योंकि साहित्य अकादमी, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास और बाल पुस्तक न्यास जैसे अनेक प्रमुख गैर-सरकारी प्रशासन गृह सभी भारतीय भाषाओं में बाल साहित्य पर पर्याप्त सामग्री का प्रकाशन कर रहे हैं।

बायोस्फेयर क्षेत्र

*254. **श्री रमा शंकर कौशिक:**
प्रो॰ रामगोपाल यादव:

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में बायोस्फेयर क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है तथा सबसे अधिक धनराशि किस क्षेत्र को प्राप्त होती है;

(ख) नंदा देवी को बायोस्फेयर क्षेत्र कब घोषित किया गया और ऐसी घोषणा के समय इसके क्या उद्देश्य थे;

(ग) क्या उद्देश्यों की प्राप्ति हो रही है, यदि हां, तो अब तक प्राप्त उद्देश्यों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन हैं और सरकार उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु एवं दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रही है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री सुरेश प्रभु): (क) देश में अब तक 11 बायोस्फेयर क्षेत्र घोषित किए गए हैं। इस मंत्रालय द्वारा प्रचालित "बायोस्फेयर क्षेत्र" स्कीम में सबसे अधिक धनराशि नीलगिरी बायोस्फेयर रिजर्व को प्राप्त हो रही है।

(ख) नंदा देवी क्षेत्र को 18.1.1988 से बायोस्फेयर क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया था। घोषणा के समय उसके उद्देश्य थे: आनुवांशिक विविधता सहित प्रतिनिधि पारि-प्रणाली का संरक्षण, आधारभूत और व्यावहारिक अनुसंधान को बढ़ावा देना तथा शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए अनुभवों का प्रचार-प्रसार।

(ग) और (घ) उद्देश्य धीरे-धीरे पूरे हो रहे हैं। क्षेत्र के बफर जोन क्षेत्रों में स्थानीय लोगों की प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भरता को कम करने के लिए विभिन्न कार्यकलापों द्वारा जीविका और रोजगार के विकल्पों को बढ़ावा दिया जा रहा है। जैसे फल और औषधीय पौधों की खेती, ऊन उद्योग का संवर्धन, पारि-पर्यटन से संबंधित गतिविधियों, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देना, मृदा संरक्षण, चारागाह प्रबन्धन तथा घास स्थलों का सुधार, स्वास्थ्य की देखभाल, पेयजल की पूर्ति तथा स्थानीय लोगों के लिए शिक्षा और जागरूकता का सृजन जैसे सामाजिक कल्याण गतिविधियों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। अनुसंधान और विकास गतिविधियों के अन्तर्गत बफर जोन में मृदा, वनस्पतिक हाइड्रोलोजिकल साइकल और सामाजिक आर्थिक अध्ययन किए जा रहे हैं।

चीनी को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत नियंत्रण से मुक्त किया जाना

*255. **श्री लक्खीराम अग्रवाल:** क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामले** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाजन समिति ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत जनसाधारण को दी जाने वाले लेवी चीनी को चरणबद्ध तरीके से नियंत्रण मुक्त करने की संस्तुति की है;

(ख) सरकार द्वारा इस संस्तुति पर क्या निर्णय लिया गया है; और

(ग) महाजन समिति की रिपोर्ट पर कब तक निर्णय ले लिए जाने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बारनाला): (क) जी हां।

(ख) और (ग) सरकार इस सिफारिश पर विचार कर रही है। ऐसी कोई समय-सीमा निर्धारित करना संभव नहीं है जिस तक महाजन समिति की सभी सिफारिशों पर निर्णय ले लिए जाने की संभावना है।

Rise in prices of Sugar in India

*256. SHRI JIBON ROY: Will the Minister of FOOD AND CONSUMR AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government attention has been drawn to the report appearing in the Economic Times (Delhi) dated 30th January, 1999, stating that India has become a dumping ground for sugar;